

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1773
10 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग में श्रमिकों का कौशल उन्नयन

1773. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात उद्योग में श्रम उत्पादकता बढ़ाने के लिए श्रमिकों के कौशल-आधारित प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस्पात उद्योग में हासिल किए गए स्वचालन किस सीमा तक हुआ है और क्षमता उपयोग और दक्षता में सुधार तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को वैश्विक इस्पात उत्पादकों के बराबर लाने के लिए स्वचालन बढ़ाने हेतु चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 'विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना' के अंतर्गत दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और उन्होंने क्या प्रोत्साहन प्राप्त किए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) इस्पात उद्योग कौशल विकास और श्रमिकों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करके श्रम उत्पादकता में सुधार कर रहा है। इसमें इन-हाउस तकनीकी और बहु-कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ उन्नत रखरखाव और स्वचालन संबंधी ज्ञान प्राप्ति शामिल है। कंपनियां विशेषज्ञता विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी भागीदारों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ भी काम कर रही हैं। डिजिटल लर्निंग, संविदागत श्रमिकों के लिए कौशल की पहचान और नेतृत्व प्रशिक्षण उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने में मदद करते हैं।

(ख) इस्पात उद्योग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग मॉडल को अपनाकर चुनिंदा शॉप फ्लोर्स पर स्वचालन और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। डिजिटल ट्विन्स जैसे उपकरण और पूर्वानुमानित रखरखाव कारखानों को अधिक कुशलता से चलाने और उपकरणों के खराब होने को कम करने में मदद कर रहे हैं। डिजिटल समाधान सप्लाय चैन और ऑफिस के काम को तेज़ और आसान बना रहे हैं। कार्य निष्पादन और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए एआई-आधारित निर्णय लेने वाले उपकरणों और बेहतर कनेक्टिविटी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

(ग) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान क्रमशः 48 करोड़ रुपये और 187.73 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई हैं। पीएलआई के पहले दौर के तहत 19 कंपनियों की 44 परियोजनाएं और पीएलआई के दूसरे दौर के तहत 25 कंपनियों की 42 परियोजनाएं शामिल हैं।
